

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोन:- 256906, 256907, फैक्स:- 01562-256908

वर्ष: 17 संख्या: 94

प्रभात

चूरू, गुरुवार 31 जुलाई, 2025

पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

## विपक्ष का मानना है, दो दिन की बहस के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मूल सवाल अनुत्तरित ही रहे

प्र. मंत्री मोदी के विस्तृत उत्तर के बाद भी, विपक्ष के अनुसार, यह बात साफ नहीं हुई कि राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम कराने में कुछ भूमिका थी या नहीं

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में दो दिन तक चली लंबी बहस और राज्यसभा में हुई दो दिन की चर्चा के बावजूद, ऑपरेशन सिंदूर, जो नृशंस पहलगाम नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी, से जुड़े विपक्ष के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं मिल सके। सरकार द्वारा इसे “पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने” की निर्णायक कार्रवाई के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन अब यह रणनीति संदेहों, कूटनीतिक उलझनों और अस्पष्टता से घिरी हुई नजर आ रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा में दिए गए विस्तृत एवं लम्बे जवाब के बावजूद, सरकार विपक्ष के मुख्य सवालों से किनारा करती दिखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कथित

- विपक्ष के अनुसार, उसे सुरक्षा संबंधी इन प्रश्नों का जवाब नहीं मिला:  
(अ) आतंकवादी पहलगाम में घुसे कैसे? और आतंकवादी हमले के बाद कहाँ गये?  
(ब) क्या सभी आतंकवादी मारे गये या कुछ अभी भी घूम रहे हैं? विपक्ष तीन आतंकवादियों को मार गिराने के सरकारी दावे को स्वीकार नहीं करता।  
(स) हवाई हमले में भारत के कितने लड़ाकू विमान खत्म हुए?  
(द) ट्रंप के तथाकथित हस्तक्षेप के बाद, भारत द्वारा जवाबी हमला रोक देने से भारत को क्या लाभ मिला ,रणनीति की दृष्टि से।

भूमिका पर सरकार से बार-बार सवाल किये, जिन्होंने कम से कम 29 बार यह दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान संघर्षविराम (सीजफायर) में अहम भूमिका निभाई। लेकिन नई दिल्ली ने न

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकीयों की पहचान, उनके मूल ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

विपक्ष ने सरकार पर बयानबाजी एवं शब्दजाल के पीछे सच्चाई को छिपाने और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का यह दावा, कि “किसी वैश्विक शक्ति ने भारत को सैन्य अभियान रोकने का निर्देश नहीं दिया”, ट्रंप के बयानों और अमेरिका सहित, अन्य वैश्विक शक्तियों द्वारा चिंता जताने के तुरंत बाद तनाव में आई कमी से मेल नहीं खाता। सरकार की सबसे बड़ी आलोचना उस समय हुई, जब पहलगाम आतंकी हमला, जिसे सबसे सीमा-पार द्वारा प्रायोजित माना था तथा जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, पर न तो कोई शोक प्रस्ताव लाया गया, और न ही सरकारी स्तर पर शोक व्यक्त किया गया। संसद में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

इसके साथ ही, हमले में शामिल पांच आतंकीयों की पहचान, उनके मूल ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध निरस्त करने पर रोक

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने डींग जिले के नगर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध तय समय से पहले निरस्त करने वाले राज्य सरकार के गत 16 जून के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में निदेशक व प्रमुख विशेष सचिव स्थानीय निकाय,

- हाई कोर्ट ने डींग जिले के नगर की अन्नपूर्णा रसोई के बारे में राज्य सरकार के 16 जून के आदेश पर रोक लगाई।

जिला कलेक्टर भरतपुर, कमिश्नर नगर निगम भरतपुर व कार्यकारी अधिकारी, डींग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने ये आदेश संकल्प शिक्षा समिति की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

‘जमानती अपराध पर बेल क्यों नहीं दी गई’

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर उन्हें जेल भेजने के मामले में संबंधित न्यायिक न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा से दो सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। इसके साथ ही, अदालत ने दोनों आरोपी महिलाओं को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मौजूद पारीक और इंदू वर्मा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

- याचिका में अधिवक्ता राजेश हाई कोर्ट ने निचली अदालत के दो न्यायिक अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

महर्षि ने अदालत को बताया कि मामले में पुलिस ने उन्हें फंसाया है और वे निर्दोष हैं। पुलिस अनुसंधान में दोनों के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध प्रमाणित माना गया है, वे धाराएं जमानती प्रकृति की हैं। इसके बावजूद, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजते समय इसका ध्यान नहीं रखा। वहीं, एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने भी 24 जून को उनके जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पत्रों में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और इस ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया, लगातार क्यों सोना खरीद रहा है?

क्या ट्रंप की लगातार टैरिफ संबंधी धमकियों व डॉलर की वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती अस्थिरता व विश्व में बढ़ रही फायनैशियल अनिश्चितता से प्रेरित है, आर.बी.आई. की सोना खरीद?

- भारत के विदेश मुद्रा के कोष में सोने का योगदान पहले 8.9 प्रतिशत ही होता था और हाल ही में हुई खरीद के बाद, सोने का योगदान बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गया है।
- हालांकि, सोने पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, सरकारी बॉण्ड्स की तुलना में। पर, जब विश्व में अशांति व अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं, ब्याज की कमाई से ज्यादा सोने द्वारा प्रदत्त फायनैशियल स्थिरता ज्यादा प्रिय लगती है।

आरबीआई पारंपरिक विदेशी मुद्रा भंडार, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, से दूरी बनाकर वैश्विक अस्थिरता के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी 8.9 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जो एक रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। और यह बदलाव केवल दिखावटी नहीं है। आर.बी.आई. की सोने की खरीददारी का समय, प्रौद्योगिकी और मात्रा इस बात का संकेत हैं कि वैश्विक आर्थिक ढांचे को लेकर गहरी

चिंता है। डिजिटल मुद्राओं और तेज़ रफ्तार बाज़ारों की आज की दुनिया में, एक समय में पुरानी मानी जाने वाली संपत्ति, सोने, की ओर यह वापसी क्यों? शायद इसलिए, क्योंकि जब हालात डगमगाने लगते हैं, तब सोना सबसे ज्यादा चमकता है। सोने को हमेशा से ही “सुरक्षित निवेश” माना गया है, खासकर तब, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था संकट में होती है। इसमें कोई काउंटरपार्टी जोखिम नहीं होता, अर्थात् इसका मूल्य किसी और ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को एक और झटका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव द्वारा दायर याचिका को अस्वीकार कर दिया

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 30 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भूमि के बदले नौकरी घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। यह मामला उनके 2004 से 2009 तक रेल मंत्री के कार्यकाल से जुड़ा है। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति नौगमीकम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका निष्प्रभावी नहीं होगी। अतः अदालत ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए लालू प्रसाद की आरोप तय करने में देरी की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने लालू की याचिका का विरोध करते हुए याचिका दायर

- याचिका में यह मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट पर रोक लगाई जाए, कि उक्त न्यायालय, लालू यादव के खिलाफ आरोप पत्र फाइनल न करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरोप पत्र दायर होने से लालू यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे में कार्यवाही पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

करने के कारण उन पर जुर्माना लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया। यह दूसरा अवसर है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को राहत देने से इन्कार किया है। इससे पहले 18 जुलाई को भी अदालत ने ट्रायल पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई उनकी हूए कहा है कि यह “भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा” है।

खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था और 12 अगस्त को अंतिम सुनवाई तय की थी। यह मामला 18 मई 2022 को सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि लालू प्रसाद ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने डींग जिले के नगर में चल रही अन्नपूर्णा रसोई का अनुबंध तय समय से पहले निरस्त करने वाले राज्य सरकार के गत 16 जून के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में निदेशक व प्रमुख विशेष सचिव स्थानीय निकाय,

जिला कलेक्टर भरतपुर, कमिश्नर नगर निगम भरतपुर व कार्यकारी अधिकारी, डींग सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने ये आदेश संकल्प शिक्षा समिति की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## नवीनतम चर्चा के अनुसार, धनखड़ आंध्र के कांग्रेस नेताओं से मिलकर चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आये, उन्हें एनडीए छोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे, जिससे मोदी सरकार अल्पमत में आकर गिर जाए

- चंद्रबाबू नायडू ने इस “साजिश” से प्र.मंत्री मोदी को अवगत कराया और धनखड़ से इस्तीफा लेने की प्रक्रिया शुरू हुई।
- यह भी कहा जा रहा है कि धनखड़ चाहते थे कि न्यायाधीश वर्मा के “इम्पीचमेंट” का प्रस्ताव, राज्यसभा में पारित हो, जिससे वे “इम्पीचमेंट” की कार्यवाही के लिए अपनी पसंद के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व एक वरिष्ठ जुरिस्ट का चयन खुद करते।
- पर, लोकसभा द्वारा 145 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहले पारित हो गया।

इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और प्रधानमंत्री मोदी को धनखड़ की योजना की जानकारी दे दी। धनखड़ संदेह के घेरे में थे, क्योंकि

उनका विभिन्न राजनीतिक दलों से नाता रहा है। वे 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनूं से जनता दल के सांसद रहे और 1990-91 में संसदीय

कार्य राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद 1991 में उन्होंने राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जाईन कर ली और अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें वे हार गए। फिर 1993 से 1998 तक वे किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक रहे। एक वरिष्ठ वकील के रूप में उन्होंने 2003 में भाजपा जाईन की और पार्टी की कानूनी समिति का नेतृत्व किया। 21 जुलाई को राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ से कथित साजिश के प्रयासों पर सवाल किया। धनखड़ ने नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिंजिजू से शिकायत की थी कि संसद भवन से लगे उनके आवास पर आने-जाने वाले लोगों की कड़ी निगरानी की जा रही है और कुछ ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## राज्य उपभोक्ता आयोग ने सहारा के प्रोजेक्ट मैनेजर को जेल भेजा

- जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने टॉक रोड पर बीलवा स्थित सहारा ग्राम सिटी मामले में दिए गए आदेश की पालना नहीं करने के, अवमानना के 56 मामलों में बुधवार को आरोपी प्रोजेक्ट मैनेजर संजय सक्सेना को 13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
- आयोग ने बीलवा स्थित सहारा सिटी के मामले में दिये गये आदेश की पालना नहीं करने के अवमानना के 56 मामलों में यह निर्णय सुनाया।

दिया। आयोग के न्यायिक सदस्य निर्मल सिंह व मुकेश और सदस्य रामनिवास सारस्वत ने यह आदेश भारतीय माहना व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर दिया। आयोग के स्थायी गिरफ्तारी वार्ंट ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ‘नागरिकता का सबूत पेश करने की जिम्मेवारी किसकी है?’

चुनाव आयोग ने जिम्मेवारी मतदाता पर डाल दी, जबकि, पहले चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति का मतदान का अधिकार छीनने से पहले कारण बताकर संतुष्ट करता था कि उस व्यक्ति का नाम मत सूची से क्यों काटा जा रहा है

- देश के 93 रिटायर्ड टॉप अफसरों ने खुला पत्र लिखकर चुनाव आयोग के इस निर्णय को प्रजातंत्र के समक्ष अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया।
- पत्र के अनुसार, भारत में आज भी अधिकतर लोगों के पास दस्तावेज नहीं होते, जो यह साबित करें कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। कमज़ोर व गरीब वर्ग के लोग तो विशेषकर इन दस्तावेजों से महरूम हैं।
- एक और अहम सवाल है जो इस पत्र में शीर्ष रिटायर्ड अफसरों ने उठाया है, क्या चुनाव आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह किसी की भी नागरिकता किसी भी कारण से रद्द कर सकता है।

मतदाता सूची को शुद्ध करने के नाम पर, मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को, खासतौर पर गरीबों और हासिए पर मौजूद लोगों को, जिनके पास

नागरिकता के पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं, वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है, “पूर्व में चुनाव

रहे नियमों को उलट दिया है और अब नागरिकता सिद्ध करने का बोझ मतदाता पर ही डाल दिया गया है। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने असंवैधानिक रूप से अपने अधिकारियों को किसी का भी नाम मतदाता सूची में जोड़ने या हटाने का अधिकार दे दिया है।

अधिकारियों ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को यह “असाधारण स्वविवेकाधारित अधिकार” दे दिया है, जिससे मतदाता “जोड़ने या हटाने के मामलों में भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ गई है।” पत्र में कहा गया है, “इस पूरी कवायद का जारी रहना तथा इसके बाद इसका पूरे देश में पहुँचना भारतीय लोकतंत्र के लिए अब तक के सबसे बड़े खतरों में से एक है और यह खतरा उस संस्था द्वारा पैदा किया जा रहा है, जिसका काम सार्वभौमिक मताधिकार व्यवस्था को मजबूत करना है। मतदाता सूची को अपडेट करना तो चुनाव आयोग का नियमित एवं सामान्य (रूटीन) कार्य है।

( शेष अंतिम पृष्ठ पर )

हाई कोर्ट ने जयपुर की दूटी सड़कों का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 30 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों पर चिंता जताते हुए कहा है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या जयपुर अपनी खूबसूरती और विरासत के लिए जाना जाने वाला गौरवशाली गुलाबी नगर बना रहेगा, या फिर अपनी ही

- सर्वे कर दो सप्ताह में तथ्यात्मक रिपोर्ट व चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करने को कहा।

बुनियादी ढांचे की कमी से दहते हुए, एक डूबते हुए शहर में बदल जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में स्वरेणरा से प्रसंज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीसी, हेरिटेज और ग्रेटर नियम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों ( शेष अंतिम पृष्ठ पर )





पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, बेदला



# फेफड़ों की अत्याधुनिक देखभाल, अब उदयपुर में पहली बार...



बेसिक और एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी

एवं उदयपुर में सर्वप्रथम थोरेकोस्कोपी सूट अब PMCH में

अब फेफड़ों से सम्बंधित उपचार के लिए नहीं जाना पड़ेगा अहमदाबाद

## पल्मोनोलॉजिस्ट्स की अनुभवी टीम



डॉ. सी.एस. पुरोहित  
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ



डॉ. सुनील कुमार  
चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी एवं क्रायो प्रोसीजर  
~~₹50000~~  
निःशुल्क

एडवांस्ड थोरेकोस्कोपी  
~~₹50000~~  
निःशुल्क



डॉ. अतुल लुहाडिया

इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एवं चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ

निःशुल्क परामर्श व जाँच

निःशुल्क भर्ती

निःशुल्क चेस्ट CT-Scan & सीटी गाइडेड लंग्स बायोप्सी

निःशुल्क X-Ray, 2D Echo

निःशुल्क ब्रोंकोस्कोपी, ICDT प्रोसीजर

निःशुल्क स्पाइरोमेट्री, DLCO

### उपलब्ध सुविधाएं

#### बेसिक ब्रोंकोस्कोपी सेवाएं

- ब्रोंकोएल्वियोलर लैवेज (BAL)
- बायोप्सी
- ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन (TBNA)
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी (TBLB)

- इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी की अत्याधुनिक तकनीकें
- स्पेशल नेगेटिव प्रेशर सूट (Negative Pressure Suite)
- 24x7 क्रिटिकल केयर और आईसीयू सुविधा
- एचडी वीडियो ब्रोंकोस्कोप एवं थोरेकोस्कोप उपकरण

#### थोरेकोस्कोपी सेवाएं

- डायग्नोस्टिक एवं थैरेप्यूटिक
- बायोप्सी • प्ल्यूरोडेसिस
- एड्हीसियोलाइसिस

#### एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोपी द्वारा उपचार

- पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी • ब्रोंकोस्कोपी इन आईसीयू
- रिजिड ब्रोंकोस्कोपी • इलेक्ट्रोकोटर
- ट्रांस ब्रोंकियल लंग क्रायोबायोप्सी (TBLC)
- क्रायो प्रक्रियाएं (क्रायो बायोप्सी, क्रायो एक्सट्रैक्शन)
- एपीसी (Argon Plasma Coagulation)
- ट्यूमर मास डिबल्किंग - वायुमार्ग से बड़ी गांठें हटाना
- फॉरेन बॉडी रिमूवल - श्वास नली में फंसी वस्तु निकालना
- भारी खून बहाव (Massive Hemoptysis) का प्रबंधन
- ग्लू थेरेपी - वायुमार्ग की ब्लीडिंग रोकने हेतु



मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना



राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना



कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESIC



जननी सुरक्षा योजना JSY

योजनाओं एवं सभी इश्योरेंस एवं TPA के कैंसलस ईलाज के लिए अधिकृत हॉस्पिटल

अंबेरी पुलिया से पेसिफिक हॉस्पिटल बेदला के लिए आने एवं जाने के लिए मरीजों को निःशुल्क वाहन की सुविधा

\*नियम व शर्तें लागू

पंजीकृत मरीज इस सुविधा का लाभ 31 अक्टूबर 2025 तक उठा सकते हैं



पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल

भीलों का बेदला, एन.एच.-27, प्रतापपुरा, अम्बेरी, उदयपुर - 313011 (राजस्थान)

फोन : 8690541110, 8239278607



# संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद ( भाईजी ) पंचतत्व में विलीन

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माणकचंद के निधन पर शोक व्यक्त किया

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं पाथेय कण पत्रिका के संरक्षक माणकचंद (भाई जी) का बुधवार को एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे एवं विगत एक माह से किडनी की बीमारी का इलाज ले रहे थे। बुधवार शाम को

- राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत अनेक गणमान्य लोगों ने अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया।

हुए प्रचारक जीवन की कठिन साधना की। माणकचंद का जन्म 2 नवम्बर 1942 को नागौर जिले के कसारी-बड़ा गांव में हुआ था। 1966 में वे पूर्णकालिक प्रचारक बने और छह दशक तक राजस्थान सहित विभिन्न स्थानों पर संगठनात्मक, बौद्धिक एवं वैचारिक कार्य में संलग्न रहे। वे पाथेय कण पत्रिका के प्रबंध संपादक के रूप में 34 वर्षों तक सक्रिय रहे। उन्होंने 1989 से पाथेय कण में प्रबंध संपादक की भूमिका निभाई और वैचारिक पत्रकारिता को नई दिशा दी। उनके संपादकीय नेतृत्व में यह पत्रिका भारतीय विचारधारा की मुखर और प्रतिष्ठित आवाज बनी।

आपातकाल के कालखंड में उन्होंने जेल यात्रा भी की और वैचारिक प्रतिबद्धता से कभी

विवर्जित नहीं हुए। संघ के प्रति उनका समर्पण, अनुशासन, संयम, सादगी और संतुलित दृष्टिकोण ने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। पाथेय कण के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र निर्माण हेतु वैचारिक चेतना का दीप प्रज्वलित किया, जो दीर्घकाल तक स्मरणीय रहेगा।

**मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी:** शर्मा ने स्व. माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा शोकाकुल परिजनों को ढांडस बंधाया। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने एवं शोकाकुल परिवार को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने स्व. माणकचंद के व्यक्तित्व को याद

कर कहा कि उनका जीवन उच्च आदर्शों और सिद्धांतों के लिए समर्पित था। समाज में राष्ट्रीय चेतना और मूल्यों के प्रसार में उनके अतुलनीय योगदान को सदैव याद किया जाएगा।

पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर देवनानी ने गहरा शोक व्यक्त किया। देवनानी ने माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पाथेय कण के संरक्षक माणकचंद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। माणकचंद के निधन का समाचार सुने ही देवनानी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। देवनानी ने अस्पताल में माणकचंद की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

# रुडी का राजनीतिक अनुभव बनाम बालियान की क्षेत्रीय पकड़

जयपुर/नई दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव (प्रशासन) पद के लिए होने वाला आगामी चुनाव राजनीतिक हलकों और मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रतिष्ठित पद के लिए मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच है। एक ओर है श्री राजीव प्रताप रूडी जो सात बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और क्लब की कार्यकारी व्यवस्था में दो दशकों से सक्रिय नेतृत्वकर्ता, जिनकी प्रशासनिक दक्षता और समावेशी दृष्टिकोण को व्यापक रूप से सराहा गया है।

दूसरी ओर है श्री संजीव बालियान, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आने वाले पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री,

- भाजपा के दो नेता आमने सामने, रुडी को मिल रहा सर्वदलीय समर्थन
- फ्रेंडली मुकाबले की आड़ में तीखी टक्कर, क्लब चुनाव बना चर्चा का केंद्र

जो क्षेत्रीय सांसदों और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के समर्थन से मैदान में हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष सरकार से समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की ओर से किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। पार्टी ने इसे फ्रेंडली मुकाबले के रूप में सांसदों के विवेक पर छोड़ दिया है।हाल ही में संसद में हुए ऑपरेशन सिंदूर पर रात्रिकालीन चर्चा के दौरान

एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। बताया जाता है कि जब सदन में सांसद मौजूद थे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्कुराते हुए श्री रूडी से पूछा कि इतनी रात को भी वोट मांग रहे हैं? और फिर स्वाभाविक जिज्ञासा से यह भी पूछा कि कैसा चल रहा है? राजनीतिक हलकों में इस प्रसंग को अधोषित समर्थन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

## विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस पर पोस्टर का विमोचन

जयपुर। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि मानव तस्करी एक गंभीर विषय है और सरकार ने इसे रोकने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

शर्मा बुधवार को पुलिस मुख्यालय में विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों की सुरक्षा विषय पर सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में भी मानव तस्करी एवं महिला तथा बाल सुरक्षा विषय के महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं।

## ‘युवाओं में लोकतंत्र की बेहतर समझ बढ़ाने की पहल’

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु शनिवार को राजस्थान विधान सभा में प्रातः 10 बजे से एक दिवसीय युवा संसद होगी। युवा संसद में जयपुर शहर के विद्यालयों के विद्यार्थी, संसद अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुये राजस्थान विधानसभा के सदन में संसदीय प्रक्रियाओं पर वाद-विवाद करेंगे। देवनानी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी राष्ट्र की दिशा तय करने वाली शक्ति है। उन्हें यदि लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रिया की सही समझ मिले, तो वे समाज के सजग प्रहरी बन सकते हैं। युवा संसद इसी दिशा में एक प्रयास है, जिससे छात्र-छात्राएँ केवल शिक्षा तक सीमित न रहकर समाज और व्यवस्था को गहराई से समझ सकें।



दिन भर बारिश का दौर जारी रहा कभी तेज तो कभी फुहार। सावन के महीने में बारिश की झड़ी लगी रहने से सूरज भी नहीं निकला। सहर के लगभग सभी इलाके में सड़के दरिया बन गई , रेलवे स्टेसन अंडर पास व खाशा कोठी पर भरा बारिश का पानी।

## 1936 विद्यालयों में मरम्मत के लिए 160 करोड़ रुपये की स्वीकृति

जयपुर। झालावाड़ के पीपलोट स्कूल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत पीड़ा का अनुभव किया है। उन्होंने परिवार के मुखिया का कर्तव्य निभाते हुए शोक की इस घड़ी में त्वरित फैसले लेकर ठोस कदम उठाए हैं जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो।

गत 25 जुलाई को हुए इस हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टर की बैठक ली, उन्हें सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए और उसी दिन शाम को साढ़े 6 बजे प्रदेश के 3,688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। प्रदेश के 1,936 विद्यालयों में मरम्मत, उन्नयन और विकास कार्यों के लिए 160 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।

मेवात, डांग, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और विधायक कोष से भी मरम्मत के लिए राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों की मरम्मत के

- हादसे के दिन ही 3688 आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया

लिए 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम शर्मा के निर्देशन में शासन और प्रशासन ने इस दुर्घटना के बाद बहुत स्विफ्ट रैसपोंस दिया। यह दिखाता है कि संकट में हम बस एक हैं और प्रत्येक संकट, खतरे को चुनौती के रूप में लेकर जीवटता के साथ इसका जवाब देना हम राजस्थानियों के जीस में है। इसमें नेतृत्व सबसे अभावशाली भूमिका निभाता है और यहां भजनलाल शर्मा ने दिखाया है कि नेतृत्व अथॉरिटी, आदेश देने से कहीं आगे की भूमिका में है और वह है, आमजन के साथ तादात्म्य कर उनकी आंकाक्षा, चिंता और आशा को शासन की आंकांक्षा, चिंता और आशा का रूप लेकर लक्ष्य को समय पर प्राप्त करें।

## मुंबई साइबर क्राइम के नाम पर 80 लाख की ठगी



सोवन मंडल

जयपुर। साइबर ठगों ने अपनी शांति चालों से अजमेर की बयासी वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और डिजिटल ऑरेंट का डर दिखाकर उनसे अस्सी लाख की भारी भरकम राशि ऐंट ली। इस हाई-प्रोफाइल मामले में राजस्थान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने मुख्य खाताधारक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बैंक खाते में ठगी की गई सारी रकम ट्रांसफर की गई थी। पुलिस अधीक्षक (साइबर क्राइम) शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि यह

घटना 23 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के बीच हुई। ठगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए महिला से संपर्क साधा और खुद को मुंबई साइबर क्राइम का अधिकारी बताया। उन्होंने महिला को डिजिटल रूप से गिरफ्तार होने का झांसा दिया और कानून की कार्रवाई से बचने के नाम पर उनसे अस्सी लाख अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए।

प्रकरण अजमेर में दर्ज होने के बाद इसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन राजस्थान, जयपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। जिसके बाद जांच में तेजी आई। साइबर थाने की विशेष टीम ने ठगी गई राशि के लेनदेन का गहन विश्लेषण किया। जांच में पाया गया कि ठगी की गई पूरी अस्सी लाख की राशि एक ही बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह खाता सोवन मंडल पुत्र संतोष (30) निवासी धूलिया हावड़ा पश्चिम बंगाल का था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सोवन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। उससे आगे की पूछताछ जारी है।

# पांच सदस्यीय कमेटी डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में करेगी संशोधन



केबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत( बांये ) ने डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से बैठक ली।

- बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व अन्य अधिकारियों ने बुथ आवंटन नीति-2021 में संशोधन के सुझाव दिए

अध्यक्षता में डेयरी सेवाओं के विस्तार एवं बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांच सदस्यीय कमेटी में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, डीएलबी के डायरेक्टर जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, आरसीडीएफ एमडी श्रुति भारद्वाज, दुग्ध संघ, जयपुर के एमडी मनीष फौजदार को शामिल किया गया है। यह कमेटी बैठक में आए सुझावों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी।

बैठक में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत व

अन्य अधिकारियों ने बुथ आवंटन नीति- 2021 में संशोधन के सुझाव दिए। इनमें बुथ आवंटन हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने, नए डेयरी बूथों के स्थान आसपास आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा गठित समिति द्वारा चिन्हित कर अंतिम सूचि जारी करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा प्रस्तावित डेयरी बुथ के लिए उसी क्षेत्र के पांच किमी. की परिधि के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता देने, सेवारत सेना के जवान के परिवारिक सदस्य को आवेदन के लिए पात्र मानने संबंधी प्रस्ताव को नई नीति में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

नए सरस पालर खोलने की

संभावनाएं तलाशेगा आरसीडीएफ बैठक के दौरान प्रदेश में नए सरस पालर खोलने के लिए आरसीडीएफ को संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं, बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर सरस पालर खोलने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि नए सरस पालर खोलने से न केवल आरसीडीएफ की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की

मंशानुसार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेशभर में 2500 नए सरस बुथ खोले जा रहे हैं। इसके तहत 2000 बुथों के लिए कुल 11536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जांच के बाद 7861 आवेदन पत्र आरसीडीएफ द्वारा अनुमोदित कर संबंधित निकायों को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा विगत वर्षों के पैडिंग 500 बुथों का निस्तारण स्थानीय निकाय स्तर पर लंबित है। इस प्रकार कुल 8361 लंबित आवेदन पत्रों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लांटेरी के जरिए कुल 2500 बुथों के आवंटन के लिए पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है।

## जमीनों को फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली गैंग के दो भूमाफिया गिरफ्तार

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारत सरकार की ओर से जन्म जमीनों को सेबी के फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली जालसाज गैंग के दो भू माफियाओं को गिरफ्तार किया है और साथ ही कर फर्जी दस्तावेज व

सील मोहरे बरामद की है। इस गिरोह में दिल्ली-हरियाणा के सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। पुलिस उपयुक्त जयपुर (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि बजाज नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए

भारत सरकार की ओर से जन्म जमीनों को सेबी के फर्जी दस्तावेज से बेचने वाली जालसाज गैंग के आरोपित भेमी कुमार तातेड (49) निवासी बिलाडा जिला जोधपुर और श्रवण रणवा उर्फ सुरेश रणवा (40) निवासी लोसल

सीकर को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपित भूमाफिया प्रमोद कुमार तातेड (39) को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में उसने सरकारी जमीन को सेबी के फर्जी दस्तावेज से सौदा कर बेचना स्वीकार किया।

# ग्रेटर निगम में चहते ठेकेदारों को मिले टैंडर, अन्य के ठेके निरस्त

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। ग्रेटर नगर निगम में चहते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अफसर खुली दरियादिली दिखा रहे हैं। चुनिंदा ठेकेदारों को तो टैंडर के कार्यादेश तो दिए जा रहे हैं, जबकि अन्य फर्मों के ठेके निरस्त किए जा रहे हैं। हालांकि अब कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी ने विवादित सभी टैंडर निरस्त करने की बात कही है। ज्ञात रहे कि पिछले दिनों हेरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी के अध्यक्ष रघुवीर शर्मा और अन्य ठेकेदारों ने आयुक्त से मुलाकात करके इस मामले की लिखित और मौखिक शिकायत की थी।

सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर नगर निगम के विद्याधर नगर जोन में पिछले दिनों नाला सफाई और नाला निर्माण के कार्य के करीब 80 से 85 लाख रुपये के दो टैंडर हुए थे, जिसमें करीब 5 प्रतिशत कम रेट पर मैसर्स श्री बिल्डर्स और अन्य फर्म को कार्यादेश अधिषापी अभियंता विविध बड़ाया ने जारी किया था।

जबकि विद्याधर नगर जोन में ही इसी तरह के नाला सफाई और नाला

- अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा पर भेदभाव का आरोप लगा रहे ठेकेदार
- ठेकेदार द्वारा ज्यादा रेट डाली गई थी, वह उंची दर पर कार्यादेश का दबाव बना रहा था, इसलिए टैंडर निरस्त किए गए: नितिन शर्मा

निर्माण व मरम्मत के अन्य करीब 4 से 5 टैंडर, जो कि मैसर्स कृष्णा बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रेक्टर्स को मिले थे, उन्हें रद्द कर दिया गया। ठेकेदार अनिल अग्रवाल का आरोप है कि अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा ने जानबूझकर ठेके रद्द किए हैं, जबकि इन टैंडर्स में तय रेट से करीब 10 से 15 प्रतिशत दर कम डाली गई थी। जो कि प्रायः प्रत्येक टैंडर में सामान्यतः आती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन टैंडरों में ग्रेटर नगर निगम का राजस्व का फायदा हो रहा था और रेट भी कम आई थी, उन्हें अधिकारियों ने निरस्त क्यों किया?

जब ठेका फर्म ने इसकी शिकायत हेरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी से की तो अध्यक्ष रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में ठेकेदारों ने आयुक्त डॉ. गौरव सैनी

से मुलाकात की। रघुवीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि ग्रेटर नगर निगम में अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा इन दिनों अपनी मनमानी पर उतरे हुए हैं। वे किसी चहते ठेकेदार को टैंडर देने के लिए कभी तो किसी निविदा को 5 प्रतिशत कम रेट पर भी खोलकर कार्यादेश संबंधित अधिशाषी अभियंताओं से दिलावा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ 10 से 20 प्रतिशत कम रेट के वाले टैंडर्स को निरस्त किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में अधीक्षण अभियंता के पास निकायानुसार 50 लाख रुपए से ऊपर के कार्यों से संबंधित पत्रावलियां भेजी जाती है, परन्तु ग्रेटर नगर निगम में इसके विपरीत छोटी से छोटी फाइलें अधीक्षण अभियंता नितिन शर्मा अपने पास मंगवा

रहे है। चाहे फिर वह 1 लाख रुपये की हो या फिर 50 लाख रुपये की। जबकि राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2015 को आदेश जारी कर एस.ओ. पी. बनायी थी। जिसमें प्रत्येक अधिकारी की वित्तीय निर्णय की क्षमता तय की गई थी।

इस मामले में अधिशाषी अभियंता नितिन शर्मा का कहना है कि ठेकेदार द्वारा ज्यादा रेट डाली गई थी, वह उंची दर पर कार्यादेश का दबाव बना रहा था, इसलिए टैंडर निरस्त किए गए हैं। जहां तक बात फाइलें मंगवाने की है तो उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किसी फाइल को जांच के लिए जरूर मंगवाया गया होगा, परंतु प्रत्येक फाइल हमारे पास नहीं आती। यह हास्यास्पद भी है कि कोई एक अधिकारी ही पूरी फाइलें अपने पास मंगवाए।

इस प्रकरण में आयुक्त डॉ. गौरव सैनी का कहना है कि जिन टैंडर्स में ज्यादा दर आयी थी, उन्हें निरस्त किया गया है। जहां तक विद्याधर नगर जोन में 5 प्रतिशत कम रेट पर कार्यादेश दिए जाने की बात है तो उस विवादित टैंडर को भी हम निरस्त करने की कार्यवाही कर रहे हैं।





